डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/4-357/2024-26

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष
सहकारी समितियां एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती हैं

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक
प्रकाशन दिनांक 1 मार्च, 2025, डिस्पेच दिनांक 1 मार्च, 2025

| वर्ष 68 | अंक 19 | भोपाल | 1 मार्च, 2025 | पृष्ठ 08 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

व्यापार-व्यवसाय में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने सहकारिता के थीमेटिक सेशन को किया संबोधित

मप्र का सीपीपीपी मॉडल देश की सहकारिता में नई क्रांति लायेगा : श्री सारंग

सीपीपीपी मॉडल की म.प्र. में शुरूआत

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि व्यापार-व्यवसाय में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। दुग्ध क्षेत्र, पर्यटन, एमएसएमई सहित हर क्षेत्र में सहकारिता का अलग ही महत्व है। सहकारिता के बिना कुछ भी संभव नहीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव जीआईएस के दूसरे दिन थीमेटिक सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से आश्वासन दिया कि जिस क्षेत्र में भी इन्वेस्टर काम करना चाहते हैं, म.प्र. सरकार उनका पूरा सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की मौजूदगी में 19 एमओयू होना क्रांतिकारी पहल है। यह सहकारिता और अर्थव्यवस्था को नया आयाम देने के लिये उपयोगी साबित होंगे।

सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने को-ऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट-पार्टनरशिप (सीपीपीपी) मॉडल की घोषणा कर सहकारिता क्षेत्र में सीपीपीपी के तहत कुल राशि 2305 करोड़ रूपये की राशि में 19 एमओयू किये गये। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि मध्यप्रदेश का सीपीपीपी मॉडल देश की सहकारिता को बदलने का काम करेगा। बिना सहकार के रोजमर्रा की जिंदगी नहीं जी सकते। सहकारिता क्षेत्र में बड़े-बड़े उद्योगपतियों को भी जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र का नेटवर्क बहुत बड़ा है। हर व्यक्ति तक पहुंच बनाने के लिए सहकारिता बड़ा माध्यम है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत@2047 के सपने को पूरा करने के लिये सहकारिता को मूल बनाया तो उस ध्येय तक पहुंचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सहकार से ही समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा।

मंत्री श्री सारंग ने सहकारिता विभाग में निवेश विंग की स्थापना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि निवेश विंग डे-टू-डे काम करेगी। वो स्वयं इसकी मॉनीटरिंग करेंगे। उन्होंने जुड रहे निवेशकों का धन्यवाद दिया और नये इन्वेस्टर से जुडने का आग्रह किया कि सभी देश और प्रदेश की इकॉनॉमी ग्रोथ में अपना योगदान दें।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री सिद्धार्थ ने कहा कि सहकारिता हमारा संस्कार है। पुराने समय से ही सहकारिता का अपना अलग महत्व है। उन्होंने बताया कि एक लाख पैक्स देशभर में है और 30 करोड़ की आबादी सहकारिता से जुड़ी हुई हैं। इस अमृतकाल में यही वह क्षेत्र है जो बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकता है। सहकारिता में पैक्स को कम्प्यूटराईजेशन का काम चल रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं विश्वास करें अगले दो वर्ष में यह समृद्धि के नये कीर्तिमान रचेगी। म.प्र. का नया सीपीपीपी मॉडल को भारत सरकार की ओर से पूरा सहयोग कर आगे बढ़ाया जायेगा।

अपर मुख्य सचिव श्री अशोक बर्णवाल ने कहा कि जीआईएस में पहली बार सहकारिता क्षेत्र को जोड़ा गया है। हर क्षेत्र में सहकारिता की समितियां है। उन्होंने बातया कि मध्यप्रदेश में एक करोड़ 9 लाख सदस्य है और 16 हजार आउटलेट का नेटवर्क है। उन्होंने निवेशकों से कहा कि म.प्र. में पैक्स हर जरूरत पूरी करेगी। यह किसानों के लिये भी लाभदायक होगा।

कार्यक्रम में रिलायंस के श्री कुमार अभिषेक, प्रतिभा सिन्टेक्स के श्री श्रेयसकर चौधरी, एग्रीविस्टा के श्री राजीव सिंह, वैधनाथ के श्री अनिरूद्ध गौर, भारतीय बीज के श्री जे.पी. सिंह, मेजेस्टिक बासमती के श्री विज्ञान लोधा, आरएम ग्रुप के श्री अनिमेष जैन, मशरूम वर्ल्ड के श्री समीर सागर, वी विन के श्री अभिषेक गुप्ता, न्यूट्रेलिस कृषि उत्पादक सहकारी समिति के श्री प्रदीप द्विवेदी, सावीर बॉयोटेक के श्री संदीप सुदन आदि ने अपने विचार साझा किये।

मध्यप्रदेश में सहकारिता क्षेत्र में एमओयू की जानकारी

- मध्यप्रदेश में सहकारिता क्षेत्र में कोऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (सीपीपीपी) मॉडल के अंतर्गत कुल राशि 2305 करोड़ रुपये की राशि के 19 एमओयू हुए हैं।
- रिलायंस द्वारा राशि 1,000 करोड़ रुपये
- वैद्यनाथ ग्रुप द्वारा निवेश का प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है।
- मैजेस्टिक बासमती राइस प्राइवेट लिमिटेड रायसेन द्वारा राशि 1000 करोड़ रुपये
- आरएम ग्रुप द्वारा राशि 100 करोड़ रुपये
- मशरूम वर्ल्ड भोपाल द्वारा राशि 100 करोड़ रुपये
- वी विन लिमिटेड भोपाल द्वारा राशि 40 करोड़ रुपये
- न्यूट्रेलिस कृषि उत्पादक सहकारी समिति नोएडा यूपी द्वारा राशि 30 करोड़ रुपये
- एग्रीविस्टा एआई प्राइवेट लिमिटेड द्वारा राशि 25 करोड़ रुपये
- सवीर बायोटेक लिमिटेड नोएडा यूपी द्वारा राशि 10 करोड़ रुपये
- ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में सहकारिता क्षेत्र में 2305 करोड़ से अधिक के एमओयू
- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मंत्री विश्वास सारंग की उपस्थिति में निवेशकों ने किये 19 एमओयू
- मध्यप्रदेश में सीपीपीपी- कोऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर होगा कार्य
- मंत्री विश्वास सारंग ने की है सीपीपीपी मॉडल की शुरुआत
- समिट में पहली बार किया गया है सहकारिता क्षेत्र का विशेष सत्र
- मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने निवेशकों को दी शुभकामनाएं
- मंत्री सारंग ने की घोषणा, सहकारिता विभाग में निवेश विंग की होगी स्थापना
- रिलायंस, वैधनाथ जैसी बड़ी कम्पनियां करेंगी सहकारिता क्षेत्र में निवेश

मध्यप्रदेश में निवेश का यही समय है और सही समय है : श्री मोदी

देश की ईवी क्रांति का लीडिंग स्टेट बना मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश मैन्युफैक्चिरिंग के नये सेक्टर्स के लिये शानदार डेस्टिनेशन

अपनी क्षमता से देश के शीर्ष पाँच राज्यों में शामिल होगा मध्यप्रदेश

प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों को दिया टेक्टाइल, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी में निवेश का मंत्र

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने की मध्यप्रदेश की 18 उद्योग फ्रैन्डली नीतियां लॉन्च

विश्व जो विश्वास भारत पर कर रहा है, भारत को वही विश्वास मध्यप्रदेश पर है

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वर्ष 2025 को "उद्योग एवं रोजगार वर्ष" के रूप में मनाने के निर्णय के लिये मुख्यमंत्री डॉ. यादव को सराहा

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के भव्य आयोजन के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव को दी बधाई

मध्यप्रदेश अगले पाँच वर्ष में राज्य की अर्थव्यवस्था को करेगा दोगुना : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

औद्योगिक विकास के साथ सनातन संस्कृति की भावना के अनुरूप सभी के आंगन रोशन करना इन्वेस्टर्स समिट का लक्ष्य

बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा निवेशक भी हमारे लिए है अतिथि

जो एक बार मध्यप्रदेश आता है, वह यहीं का होकर रह जाता है

अनंत संभावनाओं के ध्येय वाक्य के साथ आरंभ हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने किया शुभारंभ

भोपाल :प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित मध्यप्रदेश से विकसित भारत के उद्देश्य से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के भव्य आयोजन के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को बधाई दी। प्रधामनंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत के इतिहास में ऐसा अवसर पहली बार आया है, जब पूरी दुनिया भारत के लिए आशान्वित है। भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी क्षमता को सिद्ध किया है, जिसके परिणाम स्वरूप सम्पूर्ण विश्व भारत पर विश्वास प्रकट कर रहा है। प्रधामनंत्री श्री मोदी ने कहा कि यही विश्वास हम मध्यप्रदेश में अनुभव कर रहे हैं। मध्यप्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से देश का पांचवां बड़ा राज्य है, कृषि और खनन में अग्रणी है, इसके साथ ही राज्य को माँ नर्मदा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। देश में हो रहे अधोसंरचना विकास का लाभ मध्यप्रदेश को मिला है, दिल्ली, मुम्बई नेशनल हाईवे का बड़ा भाग मध्यप्रदेश से निकलता है, प्रदेश में पाँच लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क है और लॉजिस्टिक्स की यहाँ अपार संभावनाएं विद्यमान हैं। मध्यप्रदेश में हर वो क्षमता है, जो इसे देश के शीर्ष पाँच राज्यों में ला सकता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाने के लिए बधाई दी।

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के लिए 18 नई नीतियां लॉन्च

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने रिमोर्ट का बटन दबाकर प्रदेश में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के लिए लागू 18 नवीन नीतियों का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत मध्यप्रदेश उद्योग नीति 2025, एमएसएमई नीति, एक्सपोर्ट प्रमोशन नीति, लॉजिस्टिक्स नीति, स्टार्टअप नीति, मध्यप्रदेश एनीमेशन, वीआर, गैमिंग कामिक्स और विस्तारित रियलिटि नीति, जीसीसी नीति, सेमी कंडक्टर नीति, ड्रोन संवर्धन और उपयोग नीति, फिल्म पर्यटन नीति, पर्यटन नीति, पम्पड हाइड्रो स्टोरेज नीति, सिटी गैस डिस्टिब्यूशन नीति, विमानन नीति, नवकरणीय ऊर्जा नीति, स्वास्थ निवेश प्रोत्साहन नीति और एकीकृत टाउनशिप नीति शामिल हैं।

देश का कॉटन कैपिटल है मध्यप्रदेश

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने समिट में पधारे उद्योगपतियों को मध्यप्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि यहां 300 से अधिक इंडस्ट्री जोन हैं और निवेश की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश में 31 हजार मेगावॉट सरपल्स एनर्जी है, जिसमें 30 फीसदी रिन्यूएबल एनर्जी है। कुछ दिन पहले ही ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ हुआ है। एनर्जी सेक्टर में आए बूम का मध्यप्रदेश को लाभ मिला है। हाल ही में 45 हजार करोड़ रूपए लागत की केन-बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखी गई, जिससे 10 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता बढ़ेगी, परिणामस्वरूप प्रदेश में कपड़ा उद्योग और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर बढ़ेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मध्यप्रदेश को देश का कॉटन कैपिटल बताते हुए कहा कि कपड़ा उद्योग और कॉटन सप्लाय में मध्यप्रदेश, देश का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहां का मलबरी सिल्क और चंदेरी साड़ियां भी बहुत पसंद की जाती हैं। देश में बन रहे सात बड़े टेक्सटाइल पार्क में से एक मध्यप्रदेश में है। देश के टूरिज्म सेक्टर में मध्यप्रदेश अजब भी है और गजब भी है। नर्मदा के किनारे पर्यटन का पर्याप्त विकास हुआ है। प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म की भी अपार संभावनाएं हैं।

इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है मध्यप्रदेश

प्रधामनंत्री श्री मोदी ने कहा कि दो दशक पहले लोग मध्यप्रदेश में निवेश करने से डरते थे। जिस प्रदेश में बसें ठीक से नहीं चल पाती थीं, वह राज्य अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। जनवरी 2025 तक प्रदेश में दो लाख इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर्ड हुए हैं, जो दर्शाता है कि नए क्षेत्रों में भी मध्यप्रदेश निवेश आकर्षित कर रहा है। लीथियम बैटरी और न्यूक्लीयर एनर्जी में भी निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में शत-प्रतिशत रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण किया जा चुका है। रानी कमलापति स्टेशन के चित्र सभी का मन मोह रहे हैं। इसी तर्ज पर प्रदेश के 80 रेलवे स्टेशनों को विकसित किया जा रहा है। विमानन सेवा के लिए ग्वालियर और जबलपुर के एयरपोर्ट को विस्तार दिया गया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार प्रदेश की विकास दर को नई ऊँचाइयां देने के लिए निरंतर हरसंभव प्रयास कर रही है। मध्यप्रदेश में निवेश का यही समय है और सही समय है।

भारत जो कहता है - वह करके दिखाता है

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि विश्व के सामान्यजन, विशेषज्ञ और संस्थाएं भारत की ओर आशा से देख रही हैं। विश्व बैंक ने कहा है कि भारत आने वाले वर्षों में ऐसे ही गतिशील अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था ने भारत को सौर ऊर्जा का श्रेष्ठ केन्द्र कहा है। एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक सप्लाय चैन के रूप में उभर रहा है। विश्व में यह मान्यता है कि भारत जो कहता है - वह करके दिखाता है। वैश्विक स्तर पर विद्यमान यह विचार निवेशकों का उत्साह बढ़ाने के पर्याप्त आधार हैं।

टेक्सटाइल, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी आगामी वर्षों में देश के विकास को गति देंगे

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि टेक्सटाइल, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी आगामी वर्षों में देश के विकास को गति देंगे। मध्यप्रदेश सहित देश में मेडिकल टूरिज्म की अपार संभावनाए हैं। हेल्थ एंड वेलनेस क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार एमएसएमई सेक्टर को गति देने के लिए एमएसएमई केन्द्रित सप्लाई चैन को विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है और इस सेक्टर में कार्यरत उद्यमियों को प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं। "ईज-ऑफ-डूइंग बिजनेस" को प्रोत्साहित करने के लिए कई अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त किया गया है। केन्द्रीय बजट में टैक्स स्लैब को रिस्ट्रक्चर किया गया है, रिजर्व बैंक ने भी ब्याज दरें घटाई हैं।

अडाणी समूह प्रदेश में एक लाख 10 हजार करोड़ रूपए का निवेश

प्रधानमंत्री श्री मोदी की उपस्थिति में विभिन्न उद्योगपतियों और औद्योगिक समूहों के प्रतिनिधियों ने मध्यप्रदेश में औद्योगिक इकाइयों के संचालन और गतिविधियों के विस्तार के संबंध में अपने अनुभव साझा किए। इसके अंतर्गत अडाणी ग्रुप के चेयरमेन श्री गौतम अडाणी ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आना उनके लिए सौभाग्य का विषय है। अडाणी ग्रुप मध्यप्रदेश में 50 हजार करोड़ रूपए का निवेश कर चुका है। भविष्य में उनके समूह की एक लाख 10 हजार करोड़ रूपए की योजना है। यह निवेश सीमेंट, खनन और ऊर्जा क्षेत्र में होगा, इससे वर्ष 2030 तक एक लाख 20 हजार रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के साथ मल्टी स्मार्ट सिटी और एयरपोर्ट सिटी के निर्माण के लिए भी उनका समूह चर्चा कर रहा है।

बीज संघ के उत्पाद नये ब्रॉन्ड नेम और आकर्षक "लोगो" के साथ करें विक्रय

सहकारिता मंत्री श्री सारंग की अध्यक्षता में हुई बीज संघ की संचालक मण्डल की बैठक

भोपाल : सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि बीज संस्थाओं द्वारा प्रमाणित बीज के विपणन का कार्य नये ब्रॉन्ड नेम के साथ किया जाए। इसके लिये आकर्षक लोगो तैयार किया जाए। मंत्री श्री सारंग मंगलवार को मंत्रालय में राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन संघ के संचालक मण्डल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मोहम्मद सुलेमान और अपर मुख्य सचिव श्री अशोक वर्णबाल उपस्थित थे।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि पैक्स, अन्य सहकारी संस्थाओं तथा निजी व्यवसायियों के माध्यम से स्थानीय कृषकों को प्रमाणित बीज विपणन का कार्य हो। उन्होंने विपणन विशेषज्ञ एवं बीज उत्पादन से संबंधित तकनीकी विशेषज्ञ की सेवायें लेने को भी कहा। उन्होंने कहा कि क्वालिटी कंट्रोल, मार्केटिंग और पैकेजिंग पर आवश्यक ध्यान दिया जाये। इस कार्यवाही से पैक्स के 32 लाख कृषक सदस्यों, बीज सहकारी संस्थाओं के सदस्यों एवं अन्य कृषकों को बीज संघ द्वारा उच्च गुणवत्ता युक्त प्रमाणित बीज उपलब्ध कराया जा सकेगा। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि बीज

सोसायटियों को नवाचार विंग से जोड़े। कहाँ कौन-सी सोसायटी विकसित करना है। उसकी डीपीआर तैयार करें। बीज सोसायटियों की रेटिंग भी की जाये। श्री सारंग ने कहा कि बिजनेस मॉड्युल तैयार करें और बिजनेस डेव्ल पमेंट सेंटर का सेट-अप बनाए।

गुणवत्तापूर्ण बीज से फसलों की उत्पादन क्षमता में होगी वृद्धि

मंत्री सारंग ने कहा कि उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के उपयोग से किसानों के फसलों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि किसानों की खेती को उत्कृष्ट करने के लिए बीज संघ अपने ब्रांड के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराएगा। इसके लिए बीज संघ द्वारा विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाए। मंत्री सारंग ने कहा कि बीज संघ गुणवत्ता, विश्वसनीयता, स्थिरता और जलवायु अनुकूल बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करे।

बैठक में निर्णय लिया गया कि, बीज संघ प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर व्यावसायिक विकास केन्द्र स्थापित कर उनके माध्यम से अपनी गतिविधि संचालित करेगा। बीज संघ उत्पादित बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये बीज उत्पादन के विशेषज्ञों की सेवाऐं लेकर कृषकों को बीज उत्पादन के प्रशिक्षण एवं वांछित आदान उपलब्ध कराने की कार्यवाही करेगा। इससे प्रदेश के कृषकों के फसल उत्पादन में उत्पादन में वृद्धि के साथ उनकी आय में वृद्धि हो सकेगी।

बीज संघ द्वारा निर्मित गोदाम सह ग्रेडिंग संयत्रों के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये बीज उत्पादक सहकारी समितियों के अतिरिक्त अन्य सहकारी समितियों को भी लीज पर देने का निर्णय लिया गया। गोदाम सह ग्रेडिंग संयत्रों का उपयोग सहकारी क्षेत्र से जुडे कृषकों द्वारा भी उत्पादित बीज/फसल के गुणवत्ता में सुधार के लिये किया जा सकेगा। इससे कृषकों को उत्पादित फसल का लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सकेगा। यह भी निर्णय लिया गया की बीज संघ को सक्षम बनाने एवं कृषकों के हित में कार्य करने के लिये बीज संघ की एक विस्तृत कार्ययोजना शीघ्र तैयार कर क्रियान्वयन करे।

बैठक में प्रबंध संचालक मार्कफेड श्री आलोक कुमार सिंह, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं श्री मनोज पुष्प, संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास श्री अजय गुप्ता, प्रबंध संचालक बीज संघ श्री महेन्द्र दीक्षित उपस्थित थे।

गेहूँ खरीदी केन्द्र में किसानों के लिए सभी सुविधाएं सुनिश्चित करें : खाद्य मंत्री

भोपाल : खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने निर्देश दिये हैं कि रबी विपणन वर्ष 2025-26 के गेहूँ उपार्जन की अवधि के दौरान उपार्जन केन्द्रों पर आने वाले किसानों के लिए सभी पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही मिलने पर उपार्जन कार्य से जुड़े अधिकारी-कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने यह निर्देश मंत्रालय में रबी उपार्जन नीति की समीक्षा के दौरान दिये।

श्री राजपूत ने कहा कि उपार्जन केन्द्रों पर आने वाले किसानों के लिए छाया की सुविधा के लिए शेड लगवाएं जाएं तथा पीने के पानी, प्रतीक्षा कक्ष, दरियां, टेबल, कुर्सी तथा शौचालय आदि का पर्याप्त प्रबंध करें। उन्होंने निर्देश दिये कि समिति स्तर पर पर्याप्त बिजली की सुविधा, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक उपार्जन उपकरण तथा किसानों की जानकारी के लिए सूचना पटल पर उपार्जन संबंधी जानकारी प्रदर्शित करें। श्री राजपूत ने निर्देश दिये कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता लाएं ताकि गेहूँ खरीदी केन्द्रों तक अधिकतम पंजीकृत किसान अपनी फसल लेकर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि किसानों को गेहूं उपार्जन के बाद जल्द से जल्द भुगतान सुनिश्चित करें।

खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में गेहूँ खरीदी का कार्य 1 मार्च से प्रारंभ किया जाएगा जो 18 अप्रैल तक चलेगा। वहीं शेष संभागों में 17 मार्च से 5 मई 2025 तक गेहूँ खरीदी का कार्य उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से किया जाएगा।

सहकारिता मंत्री श्री सारंग को स्कॉच अवॉर्ड सौंपा

मार्कफेड को उनके फर्टिलाइजर सप्लाई चैन आईएफएसएस को प्रतिष्ठित स्कॉच अवॉर्ड

भोपाल :सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग को मंत्रालय में प्रबंध संचालक विपणन संघ श्री आलोक कुमार सिंह ने नई दिल्ली में प्राप्त "स्कॉच" अवॉर्ड सौंपा। नई दिल्ली के इण्डिया हेबिटेड सेंटर में आयोजित 100वें राष्ट्रीय स्कॉच समिट में मध्यप्रदेश के सहकारिता विभाग के राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) को उनके फर्टिलाइजर सप्लाई चैन ऑटोमेशन प्रोजेक्ट आईएफएसएस को प्रतिष्ठित स्कॉच अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। प्रबंध संचालक विपणन संघ श्री सिंह की ओर से आईएफएसएस प्रोजेक्टे हेड श्रीमती मंदिरा लोध एवं प्रोजेक्ट मैनेजर श्री नितेन्द्र सिंह द्वारा अवॉर्ड ग्रहण किया गया।

मंत्री श्री सारंग द्वारा खाद वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक का उपयोग कर उर्वरक वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के निर्देश उर्वरक वितरण की नोडल एजेंसी विपणन संघ को दिये गये थे। मंत्री श्री सारंग के नेतृत्व में विपणन संघ की आईटी टीम द्वारा आईएफएसएस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इनहाउस विकास किया गया।

इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में उर्वरक सप्लाई चैन के 6 हजार से अधिक हितधारक (सभी फर्टिलाइजर कम्पनियाँ, मार्कफेड, अपेक्स बैंक एवं उनकी 900 से अधिक ब्रांच तथा 4500 से अधिक पीएसीएस) आईएफएसएस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के सिंगल प्लेटफार्म पर कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में लगभग 60 लाख मीट्रिक टन से अधिक उर्वरक की आवक से लेकर प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों तक उर्वरक आपूर्ति की रियल टाइम पर केन्द्रीकृत मॉनीटरिंग की जा रही है। इसका उपयोग कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों तथा सभी जिला कलेक्टर द्वारा इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से किया जा रहा है। इससे कृषकों को उनकी आवश्यकतानुसार उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरक सुलभता से समय पर उपलब्ध कराया जा रहा है। उर्वरक उपलब्धता की केन्द्रीकृत मॉनीटरिंग, रैक मूव्हमेंट, उर्वरक की डिमाण्ड फोर-कास्टिंग एवं मांग पूर्ति की जानकारी आईएफएसएस पोर्टल के मोबाइल ऐप एम.पी. उर्वरक पर भी उपलब्ध है। मध्यप्रदेश में अब उर्वरक वितरण व्यवस्था पूर्णत: ऑनलाइन एवं पारदर्शी हो गयी है।

धान उत्पादक किसानों को प्रति हेक्टेयर दो हजार रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

उमरिया जिले में अटल जी की प्रतिमा का अनावरण ● उमरिया अंचल के विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार धान उत्पादक किसानों को 2000 रुपए प्रति हेक्टेयर के मान से उनके बैंक खाते में अंतरित करेगी। इसका लाभ छोटे किसानों को भी मिलेगा। किसानों के हित में प्रदेश सरकार ने पहले कोदो-कुटकी के उत्पादन पर प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया। गेहूं उत्पादक किसानों से भी 2600 रुपए प्रति क्विंटल उपज खरीदी जाएगी। दुग्ध उत्पादक किसानों से सरकार दूध खरीदेगी और उन्हें बोनस भी देगी। किसानों को सोलर पंप देकर उन्हें बिजली के बिल से भी मुक्ति दिलाई जायेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हर नगरीय निकाय में गीता भवन बनाए जाएंगे। उमरिया में सोन नदी पर 45 करोड़ रुपए की लागत से नए पुल का निर्माण होगा। एक अन्य पुल भी 32 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार को उमरिया जिले के नौरोजाबाद में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया एवं विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि अटलजी का व्यक्तित्व काफी विराट था। इस वर्ष उनकी जन्मशताब्दी मनाई जा रही है। देश में पहली बार गांव-गरीब के बारे में किसी ने सोचा तो वे श्रद्धेय वाजपेयी जी थे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से आज गांवों में आवागमन सुगम हुआ है। गांवों को विकास और शहरों से जोड़ने वाले पहले व्यक्ति भारत रत्न अटलजी ही थे, जिनके सामने संसद में पक्ष-विपक्ष के सभी नेता नतमस्तक रहते थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संकल्प लिया है कि अब 250 की आबादी वाले गांवों में भी सड़कें बनाई जाएंगी। गरीबों को पक्का मकान देने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।

गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में आनंद होना चाहिए। यह प्रदेश सरकार का संकल्प है। गरीबों का भी देश-प्रदेश में अधिकार है। समाज के वंचित वर्ग को पक्के मकान मिलने चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार गरीब, किसान, युवा और नारी कल्याण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की हैं। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025 हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री श्री मोदी पधार रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में किसी बात की कमी नहीं है। पर्याप्त बिजली और पानी है। यहां कोई भी उद्योग फल-फूल सकता है। सरकार ने

ऐसी नीतियों को मंजूरी दी है कि स्थानीय युवा भी उद्योगपति बनें और खुद कमाने के साथ दूसरों को भी रोजगार प्रदान करें। सरकार ने दो से ढाई करोड़ की फैक्ट्री लगाने पर भी अनुदान देने का प्रावधान किया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं

- उमरिया जिले के ग्राम पौड़ी में 600 मेगावॉट की ताप विद्युत परियोजना की इकाई स्थापित की जाएगी।
- बांधवगढ़ में टाइगर रिजर्व के बाहर जू का निर्माण किया जाएगा। यह इलाका भविष्य की दृष्टि से पर्यटन केंद्र बनेगा।
- बिलासपुर में कॉलेज निर्माण और भगवान विष्णु के धाम टकटई को 4 स्थानों से जोड़कर पर्यटन का केंद्र बनाया जाएगा।
- उमरिया में हॉकी खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए एस्ट्रो टर्फ बनेगी।

कृषि आधारित उद्योगों को विकसित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता - मुख्यमंत्री

प्रदेश में जैविक और प्राकृतिक खेती पर केन्द्रित उद्योग लगाएं जाएंगे

प्राकृतिक कृषि उत्पाद के लिए आदर्श जिले और विकासखंड किए जाएं विकसित

जैविक खेती करने वाले किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे सोलर पम्प

मुख्यमंत्री ने किया राज्य स्तरीय जैविक कृषि उत्पादन तथा मूल्य संवर्धन कार्यशाला का शुभारंभ

भोपाल :मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि कृषि रसायनों के असीमित प्रयोगों के कारण पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव से संरक्षण के लिये जैविक एवं प्राकृतिक कृषि तकनीकों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। प्रदेश में वर्तमान वर्ष में भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार प्राकृतिक कृषि विकास योजना के अंतर्गत लगभग 1 लाख एकड़ क्षेत्रफल में जैविक खेती करने का लक्ष्य तय कर कार्य किया जा रहा है। आगामी वर्षों में जैविक-प्राकृतिक खेती को बढ़ाकर पाँच लाख हैक्टेयर तक ले जाने का लक्ष्य रखा जाए। जैविक उत्पादों के बेहतर मूल्य किसानों को दिलाने के लिये प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर जैविक हाट-बाजार लगाए जाएं। प्रदेश में प्राकृतिक कृषि उत्पाद के लिए आदर्श जिले और विकासखंड विकसित किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में जैविक और प्राकृतिक खेती पर आधारित मेले लगाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जैविक खेती करने वाले किसानों को सोलर पम्प उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय जैविक कृषि उत्पादन तथा मूल्य संवर्धन कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समारोह स्थल पर एक जिला एक उत्पाद तथा विभिन्न विभागों और जैविक खेती के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपनी विदेश यात्राओं का उल्लेख करते हुए कहा कि पूरा विश्व प्रदूषण रहित, स्वास्थ्यकारी प्राकृतिक कृषि उत्पादों के लिए मध्यप्रदेश की ओर देख रहा है। नवीन तकनीकों से कृषि उत्पादन में वृद्धि तो होना चाहिये किन्तु पर्यावरण संरक्षण के लिए जैविक एवं प्राकृतिक खेती से प्रकृति का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह वर्ष उद्योग वर्ष घोषित किया गया है। कृषि प्रधान राज्य होने से यहाँ खेती को साथ लेकर उद्योग नीतियां लागू करना आवश्यक है। इसीलिये राज्य सरकार कृषि आधारित उद्योगों को विकसित करने पर विशेष ध्यान दे रही है। जिन जिलों में औद्योगिक दर कम हैं, वहां कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश की देश के दुग्ध उत्पादन में 9 प्रतिशत की हिस्सेदारी है, जिसे 20 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के किसानों की समृद्धि तथा आय वृद्धि के लिए राज्य सरकार भरसक प्रयास कर रही है। कृषि उत्पादकों को सब्जी उत्पाद निर्यात करने पर केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकार के सहयोग से ट्रान्सपोर्ट व्यय दिया जा रहा है। किसानों को इसका लाभ दिलाने के लिये कृषक उत्पादक संगठनों तथा स्वयं सेवी संगठनों की सहायता से चलाए जा रहे अभियान को गति दी जाए।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के पुणे में जनता सहकारी बैंक लिमिटेड की हीरक जयंती के समापन समारोह को संबोधित किया

श्रद्धेय मोरोपंत पिंगले जी ने जनता सहकारी बैंक की स्थापना कर जो बीज बोया, वो आज वट वृक्ष बनकर 10 लाख लोगों के साथ जुड़ा हुआ है

जनता सहकारी बैंक ने 'छोटे लोगों का बड़ा बैंक' के सूत्र को सार्थक किया है

आज इस बैंक की जमाराशि 9,600 करोड़ रुपए से अधिक है जो बैंक में लोगों के विश्वास को दर्शाता है

बिना पूंजी के अपने परिवार का विकास करने और देश के विकास में योगदान देने का एकमात्र रास्ता सहकारिता है

मोदी सरकार ने पिछले 3 साल में कोऑपरेटिव के मॉडल को marketable बनाते हुए cooperative development को दिशा देने का काम किया

पहली बार देश में कोऑपरेटिव क्लीयरिंग हाउस बनाने की जो कल्पना की गई है, उसे अगले 2 साल में पूरा कर लिया जाएगा

अंब्रैला संगठन बनने के बाद देश के किसी भी हिस्से में स्थित कोऑपरेटिव बैंक की क्लीयरिंग कोऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से ही होगी

नई दिल्ली| केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के पुणे में जनता सहकारी बैंक लिमिटेड की हीरक जयंती के समापन समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर केन्द्रीय सहकारिता राज्यमंत्री श्री मुरलीधर मोहोल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे और श्री अजित पवार सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

अपने संबोधन मे केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि जनता सहकारी बैंक द्वारा अर्जित किया गया विश्वास हम सबके लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि जनता सहकारी बैंक की स्थापना श्री मोरोपंत पिंगले जी ने की थी जिन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया और कभी किसी चुनौती को पीठ नहीं दिखाई। श्री शाह ने कहा कि श्रद्धेय मोरोपंत जी द्वारा बोया गया बीज आज वट वृक्ष बनकर 10 लाख लोगों के साथ जुड़ा हुआ है और ये हमारी संगठन की क्षमता औऱ अच्छे व्यवहार का परिचायक है। उन्होंने कहा कि इस बैंक ने पूरे देश में एक अच्छा संदेश दिया है कि पारदर्शिता, समर्पण औऱ निष्ठा के साथ कोई संस्था काम करती है तो वो कितना आगे बढ़ सकती है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने राष्ट्र के सामने दो संकल्प रखे हैं – 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना और 2027 तक देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनाना। उन्होंने कहा कि इन दोनों संकल्पों में अगर सहकारिता क्षेत्र का विकास नहीं होता है तो ये अधूरे रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर हर व्यक्ति का विकास न हो और हर घर में समृद्धि न हो तो ये दोनों संकल्प अधूरे रह सकते हैं। श्री शाह ने कहा कि हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार काम देना और उसे देश के विकास के साथ जोड़कर हर परिवार को समृद्ध बनाना सिर्फ सहकारिता आंदोलन के माध्यम से संभव हो रहा है।

श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गठित सहकारिता मंत्रालय का मंत्र सहकार से समृद्धि है । उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने विगत 10 साल में देश के करोड़ों लोगों के जीवन में कई आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अब ये करोड़ों लोग आगे बढ़कर देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बिना पूंजी के अपने परिवार का विकास करने और देश के विकास में योगदान देने का एकमात्र रास्ता सहकारिता है। श्री शाह ने कहा कि छोटी-छोटी पूंजी मिलाकर एक बहुत बड़ा काम करने का नाम ही सहकारिता है। उन्होंने कहा कि जनता सहकारी बैंक इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है जिसने 'छोटे लोगों का बड़ा बैंक' के सूत्र को सार्थक किया है।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 3 साल में सहकारिता आंदोलन को गति देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमने भारत के कोऑपरेटिव के मॉडल को marketable बनाया है, cooperative education को सशक्त करने के लिए हम सहकारिता विश्वविद्यालय बिल ला रहे हैं, cooperative innovation को integrate कर इसे देश के विकास की शक्ति बनाना चाहते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी ने cooperative development को दिशा देने का काम किया है।

श्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिता को आगे बढ़ाने के लिए हमें तकनीक को भी स्वीकारना होगा। उन्होंने कहा कि देश में कुल 1465 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं जिनमें से 460 सिर्फ महाराष्ट्र में हैं। उन्होंने कहा कि लंबे समय से अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए एक अंब्रैला संगठन पर विचार चल रहा था और अब इस संगठन के लिए 300 करोड़ रूपए की राशि एकत्रित करने का काम पूरा कर लिया गया है। श्री शाह ने कहा कि ये अंब्रैला संगठन कोऑपरेटिव बैंकों को हर प्रकार की सहायता देने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा कि पहली बार देश में क्लीयरिंग हाउस बनाने की कल्पना की गई है जिसे अगले 2 साल में पूरा कर लिया जाएगा।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय ने बहुत सारे काम अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के व्यापार को बढ़ाने के लिए किए हैं। उन्होंने कहा कि हमने आधार-इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को कोऑपरेटिव बैंकों के लिए खोला है, गोल्ड लोन और हाउसिंग लोन की सीमा को भी बढ़ाया है और एकमुश्त ऋण निपटान का प्रावधान भीकोऑपरेटिव बैंकों के लिए लागू होगा। उन्होंने कहा कि अंब्रैला संगठन बनने के बाद देश के किसी भी हिस्से में स्थित कोऑपरेटिव बैंक की क्लीयरिंग कोऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से ही होगी। श्री शाह ने कहा कि इसके साथ राष्ट्रीयकृत बैंक, छोटे वित्तीय बैंकों और NBFCs से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के लिए भी हम गवर्नेंस को सुदृढ़ करने और तकनीकी इनोवेशन्स को समाहित करने के लिए निगरानी की एक समिति भी बना रहे हैं।

श्री अमित शाह ने कहा कि 1949 में स्थापना के बाद जनता सहकारी बैंक 1988 में शेड्यूल्ड सहकारी बैंक बना, 2005 में इसने कोर बैंकिंग को स्वीकार किया, 2012 में मल्टीस्टेट शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक बना और देश की सबसे पहली कोऑपरेटिव डी-मैट संस्था शुरू करने का सौभाग्य भी इसे मिला। उन्होंने कहा कि 71 शाखाओं, 2 एक्सटेंशन काउंटर्स, 1,75,000 सदस्यों और 10 लाख से ज़्यादा संतुष्ट ग्राहकों के साथ ये एक बैंक नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा परिवार है। उन्होंने कहा कि आज इस बैंक की जमाराशि 9,600 करोड़ रुपए से अधिक है जो बैंक में लोगों के विश्वास को दर्शाता है। श्री शाह ने कहा कि समाज सेवा में भी जनता सहकारी बैंक ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, चाहे लातूर का भूकंप हो, कोल्हापुर-सांगली की बाढ़ हो या फिर कोविड महामारी हो।

ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुवाई के लिए यह उपयुक्त समय : कृषि मंत्री

भोपाल :किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना ने कहा है कि ग्रीष्मकालीन सब्जियों की पौध की तैयारी व बुवाई का यह उपयुक्त समय चल रहा है। बुवाई 15 फरवरी से 15 मार्च तक कर सकते हैं। ग्रीष्मकालीन सब्जियों लौकी, कद्दू, करेला, तोरई, खीरा, टिण्डा की बुवाई का यह उपयुक्त समय है।

कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इनके लिए बलुई दोमट मिट्टी, जिसका पीएच मान 6 से 7.5 के मध्य हो उपयुक्त होती है। मृदा जांच रिपोर्ट के आधार पर गोबर की खाद या कम्पोस्ट अथवा रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करें। बुवाई के लिए नालियां या जमीन से उठी हुई क्यारियां तैयार कर लें। खेत में नालियां लगभग 40-50 सेंटीमीटर चौड़ी और 30-40 सेंटीमीटर गहरी बनाएं। दो कतारों में 2 से 4 मीटर की दूरी रखें। बीज दर खीरा के लिए 2 से 2.5 किलोग्राम, लौकी की 4 से 5, करेला की 5 से 6, तोरई की 4.5 से 5, कद्दू की 3 से 4, टिण्डा की 5 से 6, तरबूज की 4 से 4.5 और खरबूज की बीज दर 2.5 किलोग्राम रखें। रोपाई से पूर्व सब्जियों के बीजों को फफूंदनाशक दवा काबेंडाजिम + मैन्कोजेब 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचार करें।

ज्यादातर बेल वाली सब्जियों में खेत की तैयारी के समय 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें।

भारत के विकास को गति दे रहा है मध्यप्रदेश : केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह

जीआईएस भोपाल के समारोह में केन्द्रीय गृह मंत्री ने की मध्यप्रदेश सरकार के नवाचारों की सराहना

जीआईएस से मिले 30.77 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

हमने निवेश के लिए बनाया है नया इको-सिस्टम

हमारी निवेश नीतियों को सबने सराहा, निवेशकों का बढ़ा है मध्यप्रदेश पर विश्वास

आरआईसी के सफल प्रयासों का प्रतिफल मिला जीआईएस में

भोपाल : केन्द्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा है कि भोपाल में सम्पन्न दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट सिफ मध्यप्रदेश की नहीं, यह देश की उपलब्धि है। उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिये उठाये गये कदम भारत के विकास को भी गति देने का कार्य कर रहे हैं। मध्यप्रदेश निश्चित ही प्रमुख उद्योग राज्य बनेगा। मध्यप्रदेश में निवेशकों में निवेश करने के प्रति विश्वास बढ़ा है। स्थायी और सशक्त सरकार, पारदर्शी प्रशासन, उपयोगी नीतियां, सहयोगी सामाजिक वातावरण, आर्थिक प्रगति के लिये ऐसे आधार हैं, जो मध्यप्रदेश में मौजूद हैं। मध्यप्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने जनविश्वास अधिनियम, ईज ऑफ डूइंग के माध्यम से पहल की है। निश्चित ही मध्यप्रदेश टॉप एचीवर बनेगा। केन्द्रीय मंत्री श्री शाह भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय परिसर में हुई दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे।

केन्द्रीय मंत्री श्री शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सूत्र वाक्य 'विरासत भी और विकास भी' को मध्यप्रदेश चरितार्थ कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वर्ष@2047 तक पूर्ण विकसित भारत का संकल्प किया है। भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। इसमें मध्यप्रदेश अपना योगदान देते हुए महत्वपूर्ण सहयोगी राज्य सिद्ध होगा। मध्यप्रदेश ने लोकल और ग्लोबल दोनों स्तर पर प्रगति के प्रयासों में सहभागी बनने का सराहनीय कार्य किया है। यह ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट बहुत सफल रही है। इसकी सफलता के लिये मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उनकी टीम बधाई और अभिनंदन की पात्र हैं। मध्यप्रदेश में इस समिट में हुए एमओयू जल्द ही मूर्त रूप लेकर प्रदेश के विकास को गति प्रदान करेंगे।

मध्यप्रदेश में किया गया प्रयोग सम विकास के लिये आवश्यक

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने कहा कि मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. द्वारा किया गया रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का प्रयोग सफल रहा। सम विकास के लिये ऐसे प्रयास आवश्यक हैं। अन्य राज्य भी यह प्रयोग कर सकते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में अलग तरह का निवेश संभव होता है। मध्यप्रदेश में फिजीकल पोटेंशियल, सेक्टोरल और ग्लोबल पोटेंशियल के मार्ग प्रशस्त हुए हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी की भावना के अनुरूप मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास का महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है।

केन्द्रीय मंत्री श्री शाह के उद्बोधन के प्रमुख बिन्दु

- मध्यप्रदेश में सशक्त अधोसंरचना मौजूद है। भूमि, जल और बिजली की पर्याप्त उपलब्धता है।
- यहां कुशल मानव संसाधन की प्रचुरता है।
- मध्यप्रदेश में मार्केट का एक्सेस और पारदर्शी प्रशासन है।
- मध्यप्रदेश में स्थिर सरकार, केन्द्रीय भौगोलिक स्थिति, उद्योगों के लिये अनुकूल नीतियां हैं।
- यहां सभी कुछ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।
- मध्यप्रदेश उद्योगपतियों के आकर्षण का प्रमुख केन्द्र है।
- मध्यप्रदेश में सर्वाधिक खनिज संसाधन उपलब्ध हैं।
- मध्यप्रदेश देश की कॉटन केपिटल है। यहां देश के कपास उत्पादन का एक चौथाई ऑर्गेनिक फार्म में होता है।
- मध्यप्रदेश में खाद्य प्र-संस्करण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य हुआ है।
- यह अत्यंत सराहनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वर्ष-2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया है।
- मध्यप्रदेश तेजी से औद्योगिक विकास की उपलब्धि प्राप्त करेगा।
- आज सम्पन्न समिट में 200 से अधिक संस्थानों के प्रतिनिधि, 60 देशों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में प्रतिभागी शामिल हुए। कई विभागीय सम्मेलन और सेक्टोरल सत्र भी समिट में सम्पन्न हुए हैं। यह मध्यप्रदेश की ग्लोबल उपस्थिति का परिचायक है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में निवेश का तैयार हुआ सकरात्मक माहौल : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय गृहमंत्री श्री शाह के जीआईएस के समापन सत्र में आने के लिए उनका अभिनंदन करते हुए कहा कि कल प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा जीआईएस का शुभारंभ और आज गृह मंत्री श्री शाह द्वारा समापन से मध्यप्रदेश ने देश के कुशल नेतृत्व का मार्गदर्शन प्राप्त किया है। उन्होंने इसके लिए मध्यप्रदेश की जनता की ओर से आभार जताया। उन्होंने निवेशकों से कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश में औद्योगीकरण और निवेश को लेकर एक सकारात्मक माहौल बना है। मप्र में पर्याप्त जल, जंगल, जमीन, बिजली, लैंड बैंक और निवेश के लिये अनुकूल वातावरण बना है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में एक वर्ष पहले क्षेत्रीय स्तर पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव (आरआईसी) की शुरुआत की थी, ताकि संभाग स्तर पर औद्योगीकरण और निवेश को और अधिक बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने कहा कि आरआईसी के बहुत अच्छे परिणाम हमें मिले हैं। आरआईसी में किए गए प्रयासों का प्रतिफल हमें जीआईएस में मिला है। हमने मध्यप्रदेश को आगे बढ़ाने और निवेशकों का हौसला बढ़ाने के लिए निवेश नीतियों में कई बदलाव किए हैं। हमारी नई निवेश नीतियों की सभी ने सराहना की है। हमारी सरकार ने वर्ष-2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया है। टेक्सटाइल, फार्मा और ऑटो उद्योग में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। विकास का इस कारवां में हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 100 से अधिक एक्सपर्टस और उद्योगपतियों सहित करीब 25000 से अधिक प्रतिभागियों ने सहभागिता की। इसमें 60 से अधिक देशों के निवेशक डेलीगेट भोपाल आए। जीआईएस करीब 5000 बिजनेस-टू-बिजनेस और 600 बिजनेस-टू-गर्वनमेंट मीटिंग्स आयोजित हुई। उन्होंने बताया कि अब तक सरकार को 30 लाख 77 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। विभिन्न एमओयू साइन किये गये। प्रदेश सरकार अपने प्रयासों को धरातल पर उतरने के लिए पूर्ण प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार यहां के युवाओं, किसानों, महिलाओं और सभी प्रकार के संभावित क्षेत्रों में विकास के इस अभियान को जारी रखेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पिछले वर्ष लागू किए गए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश में किए गए नवाचारों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक वर्ष में हम सभी नए आपराधिक कानून सुधारों को पूरी तरह लागू कर मध्यप्रदेश को देश में सबसे अच्छी कानून व्यवस्था वाले राज्य के रूप में प्रतिष्ठित कर देंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर करने की दिशा में हम गृह मंत्री श्री शाह के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में बेहतर काम करने का प्रतिबद्धता पूर्वक प्रयास कर रहे हैं।

निवेशक सरकार की सुविधाओं का लें लाभ : मुख्य सचिव श्री जैन

मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने दो दिवसीय जीआईएस का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि जीआईएस में 50 देशों के 25 डेलिगेट्स भोपाल आए। 10 केंद्रीय मंत्री भोपाल और 6 केंद्रीय सचिवों ने भी भागीदारी की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने समिट का शुभारंभ कर हम सबका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई 18 नवीन नीतियों का लोकार्पण भी किया। उन्होंने निवेशकों से आव्हान किया कि मप्र सरकार की इन नीतियों का गहनता से अध्ययन कर लें और सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का भरपूर लाभ उठाएं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने टेक्सटाइल टूरिज्म और टेक्नोलॉजी सेक्टर पर फोकस करने के लिए कहा है। 78000 करोड़ का कमिटमेंट इन्वेस्टमेंट का टेक्नोलॉजी सेक्टर में प्राप्त हुआ है। मध्यप्रदेश में टूरिज्म की बहुत संभावना है। टूरिज्म क्षेत्र में 65000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुए हैं। टेक्सटाइल सेक्टर में मध्यप्रदेश को केंद्र की ओर से धार में एक टेक्सटाइल प्रोजेक्ट मिला है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा है कि समाज में सरकार का हस्तक्षेप कम होना चाहिए।

श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) के पारंपरिक/मीठे बीजों के संबंध में समीक्षा बैठक की

नई दिल्ली | केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) के पारंपरिक/मीठे बीजों के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) पारंपरिक बीजों के संरक्षण-संवर्धन के लिए निरंतर प्रयासरत है।

बैठक के दौरान केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने खरीफ़-2025 से देश के विभिन्न क्षेत्रों के कुछ चुनिंदा पारंपरिक बीजों के जैविक उत्पादन और उनकी बाजार में व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। इन बीजों में प्रमुख बीज हैं- अमरेली बाजरा – गुजरात, उत्तराखंड गहत, उत्तराखंड मण्डुआ, बुंदेलखंड मेथी, काठिया गेहूं, मुनस्यारी राजमा, काला भट्ट, काला नमक धान की चार प्रजातियां, जूही धान बंगाल और, गोपाल भोग धान बंगाल।

श्री अमित शाह ने बैठक में इस बात पर भी बल दिया कि देश के कोने-कोने से फलों, सब्जियों और खाद्यान्नों के सभी परंपरागत/मीठे बीजों की जानकारी एकत्रित कर उनका एक विस्तृत डेटाबेस बनाया जाए और उनके संरक्षण और संवर्द्धन की व्यापक कार्ययोजना लागू की जाए।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाओं हेतु दो दिवसीय कौशल उन्नयन एवं नेतृत्व विकास प्रशिक्षण सम्पन्न

रतलाम, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल एवं रतलाम जिला सहकारी संघ के तत्वावधान में दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाओं के लिए दो दिवसीय कौशल उन्नयन एवं नेतृत्व विकास प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 14 व 15 फरवरी को ग्राम पंचेड़ में किया गया।कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सहकारी प्रशिक्षण केंद्र इंदौर के प्राचार्य दिलीप मरमट ने कहा कि शोषण से मुक्ति के लिए सहकारी आंदोलन की शुरुआत हुई। श्वेत क्रांति की शुरुआत डॉ वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में गुजरात से शुरू हुई जो पूरे भारत में पहुँची।

कार्यक्रम को पूर्व प्राचार्य के.एल.राठौर ने सम्बोधित करते हुए कहा कि दुग्ध उत्पादन में मध्यप्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है।उज्जैन में पशुपालन पर महाविद्यालय बनाया जा रहा है इससे प्रदेश में पशुपालन व दुग्ध उत्पादन में प्रदेश प्रगति करेगा।प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूर्व प्राचार्य निरंजन कुमार कसारा ,साँची दुग्ध संयंत्र के प्रबंधक अशोक बैरागी एवं प्रबन्धक पी.के.भट्ट ने भी सम्बोधित करते हुए विषयवार प्रशिक्षण दिया।कार्यक्रम में पशु चिकित्सक जे.सी.राठौर ने दुधारू पशुओं की देखभाल और उनका प्राथमिक उपचार कैसे किया जाए पर विस्तृत जानकारी दी।

कार्यक्रम के प्रारंभ में स्वागत भाषण आयोजक संस्था जिला सहकारी संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिरुद्ध शर्मा ने दिया तथा अंत मे आभार प्रदर्शन संघ के जनसम्पर्क अधिकारी पिंकेश भट्ट ने व्यक्त किया।

कार्यक्रम में दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था पंचेड़ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक मंडल के सदस्य और संस्था सदस्य विशेष रूप से उपस्थित थे।

केवलारी मछुवा सहकारी समिति मर्यादित हरदुआ चुंगल जिला दमोह में एक दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न

नौगांव। दिनांक 14 .2.2025 को सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र नौगांव जिला छतरपुर म प्र के द्वारा केवलारी मछुवा सहकारी समिति मर्यादित हरदुआ चुंगल जिला दमोह में जाकर एक दिवसीय सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण वर्ग शिविर आयोजित किया गया जिसमें समिति अध्यक्ष श्री भावसिह ठाकुर सदस्य श्री दौलत रैकवार इत्यादि सदस्य आवश्यक रूप से बड़ी संख्या में उपस्थित रहे शिविर का संचालन बाबूलाल कुशवाहा जिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र नौगांव जिला छतरपुर म प्र के द्वारा किया गया।प्रशिक्षण में सहकारी अधिनियम, सहकारिता के सिद्धांत, के बारे में विस्तार से बताया गया।

सहकारी समिति मर्यादित बांदकपुर जिला दमोह में एक दिवसीय सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण सम्पन्न

नौगांव। दिनांक 15.2.2025 को सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र नौगांव जिला छतरपुर म प्र के द्वारा सहकारी समिति मर्यादित बांदकपुर जिला दमोह में जाकर एक दिवसीय सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण वर्ग शिविर आयोजित किया गया जिसमें समिति सचिव श्री नीरज यादव सदस्य श्री प्रदीप लखेरा रोशन यादव इत्यादि सदस्य आवश्यक रूप से बड़ी संख्या में उपस्थित रहे शिविर का संचालन बाबूलाल कुशवाहा जिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक ने किया। श्री बाबूलाल कुशवाह द्वारा संचालक मण्डिल के कार्य संचालन एवं उनके अधिकार के बारे में विस्ता र से बताया गया।

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा प्रायोजित तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पुणे में संपन्न

नई दिल्ली| भारत सरकार एक राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना कर रही है, जिसके लिए बजट सत्र में लोक सभा के समक्ष विधेयक प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा, इसे अगले सत्र में अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। यह जानकारी पुणे में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल ने दी। श्री मोहोल ने आगे कहा कि भारत सरकार शुरू से ही इस विश्वास और लक्ष्य के साथ प्रयासरत रही है कि सहयोग के माध्यम से समृद्धि प्राप्त की जा सकती है।

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा पुणे स्थित वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी समिति (वैमनीकॉम) में आयोजित तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनसंपन्न हुआ। सम्मेलन का विषय था 'सहकारिता के माध्यम से समृद्धि का सृजन: डिजिटल नवाचार और मूल्य श्रृंखला'। इस अवसर पर श्री मुरलीधर मोहोल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

इस अवसर पर श्री मोहोल ने आगे कहा- "सहकारिता क्षेत्र ने ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास को बढ़ावा दिया है। सरकार ने सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं।"

केंद्रीय सहकारिता एवं नागर विमानन राज्य मंत्री श्री मोहोल ने बताया कि पुणे में आयोजित सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्षमें सरकार द्वारा आयोजित पहला आयोजन था।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष (आईवाईसी-2025) घोषित किया है। इस वर्ष का विषय है "सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण कर रही हैं।"

श्री मोहोल ने सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए सीआईसीटीएबी और वैमनीकॉम की सराहना की। उन्होंने आगे कहा कि एशिया और अफ्रीका के साझेदार देशों के साथ सहयोग के क्षेत्र में संबंधों को और मजबूत किया जाएगा। सम्मेलन में 12 देशों - नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, लाओ पीडीआर, कंबोडिया, गाम्बिया, केन्या, लाइबेरिया, मॉरीशस, नामीबिया, श्रीलंका और जाम्बिया के लगभग 36 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

तीन दिनों के दौरान, विशेषज्ञों ने सहकारी समितियों में डिजिटल नवाचार, सफल सहकारी समितियों का परिचय, मूल्य श्रृंखला में चुनौतियां और अवसर, सहकारी समितियों में स्थिरता, सहकारी समितियों के माध्यम से समृद्धि, वैश्विक सहयोग आदि विषयों पर मार्गदर्शन प्रदान किया।

इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में डॉ. उमा कांत दाश, निदेशक, ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आनंद, गुजरात शामिल थे; निदेशक, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान, पुणे, प्रो. पार्थ रे; लाओ पीडीआर

(लाओस) के ग्रामीण विकास, कृषि और वानिकी मंत्रालय के उप महानिदेशक अनौसाक फंगथिमांग और गाम्बिया सहकारी समितियों के महापंजीयक अब्बा गेब्रियल संकारेह भी उपस्थित थे। सम्मेलन का आयोजन कृषि बैंकिंग में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र (सीआईसीटीएबी) द्वारा वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी समिति के सहयोग से किया गया था। वीएमएनआईकॉम और सीआईसीटीएबी पुणे की निदेशक डॉ. हेमा यादव ने सम्मेलन के तीन दिनों का अवलोकन दिया।

वनोपज सहकारी समिति मर्यादित पाटन जिला जबलपुर में एक दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न

जबलपुर। 21.02.2025 को सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर द्वार वनोपज सहकारी समिति मर्यादित पाटन जिला जबलपुर में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें समिति के प्रबंधक श्री अजीत यादव के साथ अन्य सदस्यों ने भाग लिया। प्रशिक्षण में सदस्य एवं संभावी सदस्यों तथा कर्मचारियों को प्रासंगिक विषयों तथा कार्य से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन पर एवं बिभिन्न प्रकार के सायबर अपराध से बचने के उपयो पर चर्चा की।

मछुआ सहकारी समिति मर्यादित छाताकलां जिला छिंदवाड़ा में एक दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न

जबलपुर। दिनांक 24.02.2025 को सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर द्वार मछुआ सहकारी समिति मर्यादित छाताकलां जिला छिंदवाड़ा में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें समिति के अध्यक्ष के साथ अन्य सदस्यों ने भाग लिया। प्रशिक्षण में सदस्य एवं संभावी सदस्यों तथा कर्मचारियों को प्रासंगिक विषयों तथा कार्य से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन पर एवं बिभिन्न प्रकार के सायबर अपराध से बचने के उपयो पर चर्चा की।

बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था (बी .पैक्स), नहाल्दा में प्रशिक्षण सम्पन्न

इंदौर। सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, इंदौर में जिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक राहुल श्रीवास द्वारा दिनाँक 24/02/2025 को बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था (बी. पैक्स), नहाल्दा ज़िला - खंडवा में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान संस्था के लिपिक श्री रितेश सोनी जी,ऑपरेटर श्री शिवपाल कदम जी, सेल्समैंन श्री श्याम सिंह ठाकुर एवं समस्त सम्माननीय सदस्य उपस्थित रहे। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान सहकारिता की आवश्यकता,सहकारिता की पृष्ठभूमि के बारे में बताया गया,सहकारिता में नवाचार, नवीन सहकारी नीतियों से अवगत कराया गया। सहकारिता सिद्धांत, मूल्य, विजन, मिशन, सदस्यों के अधिकारों एवं कर्तव्यों की महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। उदेश्य पर जानकारी से अवगत कराया गया। कार्यक्रम समापन पर, आभार व्यक्त किया गया।

सहकारिता से महिलाओं और संस्थानों की दक्षता में वृद्धि

जबलपुर में दो दिवसीय कौशल उन्नयन एवं नेतृत्व विकास प्रशिक्षण संपन्न

जबलपुर। सहकारिता के माध्यम से महिलाओं और सहकारी संस्थानों की दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से जबलपुर स्थित सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, कंटगा में दो दिवसीय कौशल उन्नयन एवं नेतृत्व विकास प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और सहकारिता से जुड़कर आत्मनिर्भर बनने के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त किया।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में सहकारिता की भूमिका

कार्यक्रम के समापन सत्र में दुग्ध संघ सांची के महाप्रबंधक श्री कमल यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में अपने विचार रखते हुए कहा कि महिलाओं का संगठित होकर आर्थिक गतिविधियों में भाग लेना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि यदि महिलाएँ सहकारी समितियों का गठन कर विभिन्न उपयोगी कार्यों में संलग्न होती हैं, तो वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति कर सकती हैं।

विशेष अतिथि सहकारी प्रशिक्षण केंद्र जबलपुर के पूर्व प्राचार्य श्री यशोवर्धन पाठक ने कहा कि सहकारी समितियाँ महिलाओं को एक सशक्त आर्थिक आधार प्रदान कर सकती हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि महिलाएँ सहकारी गतिविधियों में दक्षता हासिल करें और प्रशिक्षण के माध्यम से अपने कौशल को निखारें।

सहकारी संस्थानों की दक्षता बढ़ाने पर जोर

कार्यक्रम में सहकारी संस्थाओं की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए सहकारी अधिनियम 1960, वित्तीय अनुशासन, प्रशासनिक दक्षता और प्रबंधन तकनीकों पर विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए। वक्ताओं ने बताया कि सहकारी संस्थाओं में पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और आधुनिक प्रबंधन तकनीकों को अपनाने से उनकी कार्यक्षमता और प्रभावशीलता में वृद्धि होगी।

विशेषज्ञों ने सहकारी संगठनों को डिजिटल परिवर्तन अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे संस्थानों की कार्यप्रणाली अधिक सुव्यवस्थित होगी और प्रतिस्पर्धा में बनाए रखना संभव होगा। डिजिटलीकरण से लेन-देन की प्रक्रिया आसान होगी और कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।

महिला सहभागिता और सहकारी समितियों की भूमिका

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों (SHG)की भूमिका को रेखांकित किया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि महिलाओं को सहकारी संगठनों के माध्यम से व्यवसाय प्रबंधन, विपणन और नेतृत्व की शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए, जिनमें महिलाओं को कृषि, कुटीर उद्योग, सेवा क्षेत्र और वित्तीय साक्षरता से जुड़ी जानकारी दी गई।

महिला सहभागियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि सहकारी समितियों के माध्यम से उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सम्मान प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर विशेषज्ञों ने सहकारी संगठनों को और अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाने की जरूरत पर बल दिया, जिससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के और अधिक अवसर मिल सकें।

प्रशिक्षण सत्र और विशेषज्ञों का मार्गदर्शन

प्रशिक्षण सत्र का उद्घाटन मास्टर ट्रेनर श्रीमती मोनिका मुद्गल के प्रभावी उद्बोधन के साथ हुआ। इस अवसर परजिला सहकारी संघ के प्रबंधक श्री राकेश वाजपेयी ने भी महिलाओं को शासन और सहकारिता से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान कीं।

प्रशिक्षण सत्र के दौरान विषय विशेषज्ञों ने विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी दी।

इन विशेषज्ञों में –

- सहकारी प्रशिक्षण केंद्र के प्राचार्य श्री व्ही. के. बर्वे
- पूर्व प्राचार्य श्री यशोवर्धन पाठक
- मास्टर ट्रेनर श्रीमती मोनिका मुद्गल
- श्रीमती किरण भारद्वाज
- जिला सहकारी संघ के प्रबंधक श्री राकेश वाजपेयी
- केन्द्र के प्रशिक्षक श्री पीयूष राय, श्री जय कुमार दुबे, श्री अखिलेश उपाध्याय

इन सभी विशेषज्ञों ने सहकारिता से जुड़ी योजनाओं, वित्तीय प्रबंधन, विपणन रणनीतियों और नेतृत्व विकास पर मार्गदर्शन दिया।

समाज और अर्थव्यवस्था में सहकारी संगठनों की भूमिका

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि सहकारी संस्थाएं और महिला सहकारी समितियां ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन आवश्यक है, जिससे संस्थानों और व्यक्तियों दोनों की दक्षता बढ़े।

कार्यक्रम का संचालन एवं समापन

कार्यक्रम का संचालन प्रशिक्षक श्री जय कुमार दुबे द्वारा किया गया, जबकि अंत मेंआभार प्रदर्शन श्री एन. पी. दुबेने किया। इस प्रशिक्षण के सफल आयोजन से यह स्पष्ट हुआ कि सहकारिता के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जबलपुर सहकारी प्रशिक्षण केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

यह प्रशिक्षण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देने के साथ-साथ उन्हें संगठित होकर सहकारी समितियों के माध्यम से अपने आर्थिक और सामाजिक जीवन को सशक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा।

"सहकारिता से समृद्धि" के लक्ष्य को साकार करने के लिए यह पहल मील का पत्थर साबित होगी।

कौशल उन्नयन एवं नेतृत्व विकास कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न

भिण्ड, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल एवं जिला सहकारी संघ मर्यादित, भिण्ड के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय कौशल उन्नयन एवं नेतृत्व विकास कार्यक्रम जिला सहकारी संघ मर्यादित, भिण्ड के परिसर में किया गया। यह कार्यक्रम 21 फरवरी 2025 से 22 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया, जिसमें सहकारी संस्थाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन एवं मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुआ। इस अवसर पर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, शाखा बरोही के शाखा प्रबंधक श्री के एम मोर्य, मप्र राज्य सहकारी संघ के प्रशिक्षक श्री हृदेश कुमार, तथा जिला सहकारी संघ मर्यादित, भिण्ड के पूर्व प्रबंधक श्री निर्पत सिंह भदौरिया उपस्थित रहे।जिला सहकारी संघ भिण्ड के प्रबंधक श्री रामकुमार शर्मा ने सभी अतिथि व्याख्याताओं का पुष्पमालाओं से स्वागत किया एवं उन्होंने उपस्थित प्रतिभागियों को कार्यक्रम के उद्देश्यों व सहकारिता के महत्व के बारे में बताया।

कार्यक्रम के दौरान, जिला सहकारी बैंक, शाखा बरोही के प्रबंधक श्री के एम मोर्य ने सहकारी बैंकों की महत्वाकांक्षी योजनाओं एवं बैंकिंग से संबंधित विषयों पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने सहकारी बैंकिंग प्रणाली की उपयोगिता एवं सहकारी समितियों की भूमिका पर प्रकाश डाला। उनके व्याख्यान में बैंकिंग प्रणाली को प्रभावी बनाने हेतु डिजिटल बैंकिंग, ऋण योजनाएं एवं वित्तीय प्रबंधन पर विशेष जोर दिया गया।मप्र राज्य सहकारी संघ के प्रशिक्षक श्री हृदेश कुमार राय ने सहकारी संस्थाओं में सदस्यों के अधिकार, कर्तव्य एवं नवाचार पर विस्तृत जानकारी दीएवं सीएचसीडीएस (CHCDS) से संबंधित विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की तथा सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नवाचार अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

पूर्व प्रबंधक, जिला सहकारी संघ मर्यादित, भिण्ड, श्री निर्पत सिंह भदौरिया ने सहकारिता के मूल सिद्धांतों एवं कृषि संबंधी जानकारियों पर व्याख्यान दिया। उन्होंने सहकारी संस्थाओं की भूमिका एवं उनके महत्व को रेखांकित किया। उनके व्याख्यान में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों की भूमिका एवं उनकी कार्यप्रणाली को सुधारने हेतु उपायों पर चर्चा की गई।

कार्यक्रम के समापन अवसर पर जिला सहकारी संघ के प्रबंधक श्री रामकुमार शर्मा ने सहकारिता के माध्यम से समृद्धि एवं सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।